ICMR. The other thing is that it is the responsibility of the State Governments. The State Government should be requested or instructed, or whatever the language that could be used, to establish their own research centres in the Health department.

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, जहां तक आर० एंड डी० का सवाल है, रिसर्च एंड डवलपमेंट का, हैल्थ सेक्टर के लिए प्राइरिटी सेक्टर है, बहुत बड़ी प्राथमिकता की चीज है और इसलिए डी०जी०, आई०सी०एम०आर० के नीचे जितने रिसर्च यूनिट लगे हुए हैं। वे लगातार शोध, रिसर्च इस पर कर रहे है। फंड का कोई कन्स्ट्रेंट उनके पास नहीं है। भारत सरकार उन्हें इतना फंड देती है कि वह अपनी रिसर्च की गतिविधियां जारी रख सकें।

*85. *[The questioner (Shrimati Vanga Geeta) was absent. For answer vide pages 52-53].*

श्री सभापति: प्रश्न संख्या 86, श्री गया सिंह।

विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामले

86. **श्री गया सिंह:** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न न्यायालयों में कितने मामले लंबित हैं; और

(ख) इन मामलों के निपटान हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) ब्यौरा विवरण I और II पर है। (नीचे **देखिए**)

(ख) सरकार और न्यायपालिका दोनों न्यायालयों में लंबित मामलों की बड़ी संख्या के प्रति चिंतित है। मामलों के शीघ्र निपटने के लिए सरकार बहुत से उपाय किए हैं। उच्च न्यायालयों से प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के लिए मलिमथ समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए अनुरोध किया गया है जिससे, अन्य बातों के साथ-साथ, लंबित मामलों का निपटान शीघ्र होगा। सरकार, न्यायालयों में बकाया मामलों के संचयन का निरंतर पुनर्विलोकन करती रही है। प्रत्येक तीन वर्ष पर उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या का पुनर्विलोकन और उसे बढ़ाने के अतिरिक्त, सरकार ने विवाद समाधान की वैकल्पिक पद्धतियां, जिनके अंतर्गत सुलह, मध्यस्था और माध्यस्थम् भी हैं, बनाई हैं/उन्हें बढ़ावा दिया है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, राज्य प्रशासनिक अधिकरण, आयकर अपील अधिकरण, श्रम न्यायालय,

उपभोक्ता न्यायालय आदि जैसे विशेष अधिकरणों की स्थापना की गई है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए मामला सूची तैयार करने, वादकारों/अधिवक्ताओं को जानकारी उपलब्ध कराने, आदि के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। दिल्ली, चैन्नई, कलकत्ता और मुंबई के प्रमुख चार महानगरों में नगर न्यायालयों के नेटवर्किंग और कंप्यूटरीकरण के लिए एक आदर्श के रूप में एक अग्रणी परियोजना आरंभ की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य, न्यायालयों की क्षमता को बढ़ाना और सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से बेहतर न्यायालय प्रबंध के माध्यम से उनके निपटारे में शीघ्रता लाना है।

सिविल प्रक्रिया संहिता का संशोधन किया गया है और संशोधनों को तारीख 1.7.2002 से प्रवृत्त किया गया है, जिनके अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी पक्षकार को मंजूर किए जा सकने वाले स्थगनों की संख्या को तीन तक सीमित करना, स्पीड पोस्ट, कुरियर सेवाओं, फैक्स या ई-मेल द्वारा आदेशिकाओं की शीघ्र तामील का उपबंध करना, न्यायालयों को मौखिक बहस के लिए समय-सीमा नियत करने के लिए प्राधिकृत करना और मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई अन्य उपायों का उपबंध करना भी है। लोक उपयोगिताओं से संबंधित विवादों के शीघ्र समाधान के लिए स्थायी लोक अदालतें स्थापित की जा रही हैं।

विलंबित मामलों और विशेष तौर पर ऐसे विचारणाधीन व्यक्तियों के मामलों जो दीर्घावधि से जेल में हैं के शीघ्र विचारण के लिए त्वरित निपटान न्यायालय स्थापित किए गए हैं।

राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों से जिला/अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों/मजिस्ट्रेटों और समर्थक कर्मचारिवृंद के विभिन्न पदों को भरने के लिए अनुरोध किया गया है।

विवरण -I

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में
लंबित मामलों की संख्या उपदर्शित करने वाला विवरण

क्रम सं॰		लंबित मामलों की संख्या		निम्नलिखित तारीख को
		दांडिक	सिविल	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	उच्चतम न्यायालय	4747	19634	1.11.2002
उच्च न्यायालय				
1.	इलाहाबाद	149587	760054	31.3.2002
2.	आंध्र प्रदेश	10863	152649	31.3.2002

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	बंबई	27936	265344	30.9.2001
4.	कलकत्ता	36433	190697	31.3.2002
5.	दिल्ली	17718	73414	31.12.2002
6.	गुवाहाटी	5629	39413	31.12.2002
7.	गुजरात	19526	120041	31.12.2002
8.	हिमाचल प्रदेश	4037	13910	31.3.2002
9.	जम्मू-कश्मीर	1740	31625	31.3.2002
10.	कर्नाटक	7417	87819	31.3.2002
11.	केरल	17107	393972	31.3.2002
12.	मध्य प्रदेश	46121	84530	31.3.2002
13.	मद्रास	33258	314562	31.12.2001
14.	उड़ीसा	10598	137168	31.3.2002
15.	पटना	17297	63942	31.3.2002
16.	पंजाब और हरियाणा	44487	188288	31.3.2002
17.	राजस्थान	27718	110406	31.12.2001
18.	सिक्किम	20	102	31.3.2002
19.	उत्तरांचल	5365	25479	31.8.2002
20.	झारखंड	5437	9028	31.12.2001
21.	छत्तीसगढ़	16948	22690	31.10.2002
	योग	**488130**	**3062443**	

विवरण-II

जिला/अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की राज्य-वार संख्या

(31.12.2002 को यथाविद्यमान)

क्रम. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	निम्नलिखित तारीख को	सिविल	दांडिक	योग
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	06/2002	470719	397325	868044
2.	अरूणाचल प्रदेश	06/99	331	1469	1800

1	2	3	4	5	6
3.	असम	06/2001	37229	118424	155653
4.	बिहार	06/2001	207417	809789	1017206
5.	छत्तीसगढ़	12/2001	50657	143667	194324
6.	गोवा	6/2002	24687*	11367	36054
7.	गुजरात	6/2002	719166	2524734	3243900
8.	हरियाणा	12/2000	196851	323948	520799
9.	हिमाचल प्रदेश	6/2001	69976	73194	143170
10.	जम्मू-कश्मीर	12/99	43418	82596	126014
11.	कर्नाटक	12/2001	592380	398960	991340
12.	केरल	12/2001	229714	437266	666980
13.	मध्य प्रदेश	12/2001	294191	844829	1139020
14.	महाराष्ट्र	6/2002	927296	2185648	3112944
15.	मणिपुर	12/2000	4278	3487	7765
16.	मेघालय	12/99	1561	11322	12883
17.	मिजोरम	12/2000	817	986	1803
18.	नागालैंड		[उपलब्ध नहीं है]		
19.	उड़ीसा	12/2001	143142	555017	698159
20.	पंजाब	12/2000	212173	255975	468148
21.	राजस्थान	06/2001	274277	558083	832360
22.	सिक्किम	12/98	467	1352	1819
23.	तमिलनाडु	06/2001	593703	267601	861304
24.	त्रिपुरा	6/2002	6856	15164	22020
25.	उत्तर प्रदेश	6/2001	1073234	2431929	3505163
26.	पश्चिमी बंगाल	12/99	473325	861754	1335079
27.	अंदमान और निकोबार	12/99	580	26790	27370

1	2	3	4	5	6
28.	चंडीगढ़	6/2000	15215	33349	48564
29.	दादरा और नागर हवेली	6/2002	484	2215	2619
30.	दमन और दीव	12/2001	652	711	1363
31.	दिल्ली	6/2002	145851	543981	689832
32.	लक्षद्वीप	6/2002	73	57	130
33.	पांडिचेरी	6/2002	6791	7630	14421
	कुल:		6817511	13930619	20748130

Pending cases in various courts

†*86. SHRI GAYA SINGH: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) the number of cases pending in various courts of the country; and

(b) the steps being taken for disposal of such cases?

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI ARUN JAITLEY): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Details are given in Statement I and II. (*See* below)

(b) Both Government and Judiciary are concerned about the huge pendency of cases in courts. A series of steps have been taken by the Government for the speedy disposal of cases. High Courts have been requested to implement the recommendations of the Malimath Committee to streamline procedure which will, inter-alia, expedite

†Original notice of the question was received in Hindi.

disposal of pending cases. Government have also been constantly reviewing the accumulation of arrears in courts. Besides reviewing and increasing judge strength of High Courts every three years, Government have set up/encouraged alternative models of dispute resolution including conciliaton, mediation and arbitration. Special tribunals like Central Administrative Tribunal, State Administrative Tribunals, Income Tax Appellate Tribunal, Labour Courts, Consumer Courts etc., have been set up to expedite the disposal of cases. Information Technology is being used in generation of causelists, providing information to the litigants/advocates etc., for speedy disposal of cases. A Pilot project has been started for Networking and Computerisation of City Courts in the four major metrocities of Delhi, Chennai, Kolkata and Mumbai to serve as a model. The project is aimed at augmenting capacities of courts and speeding up their disposal through better court management with the help of information technology.

Civil Procedure Code has been amended and the amendments have been brought into force with effect from 1.07.2002 which, inter-alia, limit the number of adjournments which can be granted to a party to three, provide for speedy process service by speed post, courier service, fax or e-mail, authorise the court to fix time limit for oral arguments and provide for a number of other measures aimed at ensuring expeditious disposal of cases. Permanent Lok Adalats are being set up for expeditious resolution of disputes relating to public utilities.

Fast Track Courts have been set up to speed up the trial of delayed cases, and in particular the cases of undertrials who have been in jail for a long time.

State Governments and Union Territories have been requested to fill up vacant posts of judges/magistrates and supporting staff in District/ Subordinate Courts.

Statement-I

Statement indicating number of cases pending in Supreme Court and High Courts

Sl No		Pendency of cases		As on
		Criminal	Civil	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Supreme Court	**4747**	**19634**	**1/11/2002**
High court				
1.	Allahabad	149587	760054	31/3/2002
2.	Andhra Pradesh	10863	152649	31/3/2002
3.	Bombay	27936	265344	30/9/2001
4.	Calcutta	36433	190697	31/3/2002
5.	Delhi	17718	73414	31/12/2000
6.	Gauhati	5629	39413	31/12/2000
7.	Gujarat	19526	120041	31/12/2000
8.	Himachal Pradesh	4037	13910	31/3/2002
9.	Jammu & Kashmir	1740	31625	31/3/2002
10.	Karnataka	7417	87819	31/3/2002
11.	Kerala	17107	393972	31/3/2002
12.	Madhya Pradesh	46121	84530	31/3/2002
13.	Madras	33258	314562	31/12/2001
14.	Orissa	10598	137168	31/3/2002
15.	Patna	17297	63942	1/3/2002
16.	Punjab & Haryana	44487	188288	31/3/2002
17.	Rajasthan	27718	110406	31/12/2001
18.	Sikkim	20	102	31/3/2002
19.	Uttaranchal	5365	25479	31/8/2002
20.	Jharkhand	5437	9028	31/12/2001
21.	Chhattisgarh	16948	22690	31/10/2002
	TOTAL:	**488130**	**3062443**	

Statement-II

State wise pendency of cases in the District/Subordinate Courts
(As on 31.12.2002)

Sl. No.	Name of States/UTs	As on	Civil	Criminal	Total
1	2	3	4	5	6
1.	Andhra Pradesh	06/2002	470719	397325	868044
2.	Arunachal Pradesh	06/99	331	1469	1800
3.	Assam	06/2001	37229	118424	155653
4.	Bihar	06/2001	207417	809789	1017206
5.	Chhattisgarh	12/2001	50657	143667	194324
6.	Goa	6/2002	24687	11367	36054
7.	Gujarat	6/2002	719166	2524734	3243900
8.	Haryana	12/2000	196851	323948	520799
9.	Himachal Pradesh	6/2001	69976	73194	143170
10	Jammu & Kashmir	12/99	43418	82596	126014
11.	Karnataka	12/2001	592380	398960	991340
12.	Kerala	12/2001	229714	437266	666980
13.	Madhya Pradesh	12/2001	294191	844829	1139020
14.	Maharashtra	6/2002	927296	2185648	3112944
15.	Manipur	12/2000	4278	3487	7765
16.	Meghalaya	12/99	1561	11322	12883
17.	Mizoram	12/2000	817	986	1803
18.	Nagaland	Not available			
19.	Orissa	12/2001	143142	555017	698159
20.	Punjab	12/2000	212173	255975	468148
21.	Rajasthan	06/2001	274277	558083	832360
22.	Sikkim	12/98	467	1352	1819
23.	Tamil Nadu	06/2001	593703	267601	861304
24.	Tripura	6/2002	6856	15164	22020
25.	Uttar Pradesh	6/2001	1073234	2431929	3505163
26.	West Bengal	12/99	473325	861754	1335079
27.	And. & Nicobar	12/99	580	26790	27370
28.	Chandigarh	6/2000	15215	33349	48564
29.	Dadra & N. Haveli	6/2002	484	2215	2619

1	2	3	4	5	6
30.	Daman & Diu	12/2001	652	711	1363
31.	Delhi	6/2002	145851	543981	689832
32.	Lakshadweep	6/2002	73	57	130
33.	Pondicherry	6/2002	6791	7630	14421
	TOTAL		6817511	13930619	20748130

श्री गया सिंह: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कानून मंत्री जी से जानना चाहता हूं। उन्होंने जो जवाब दिया है उसके अनुसार सिविल कोर्ट में 68 लाख से ज्यादा मुकदमें अभी लंबित हैं और क्राइम के करीब 1 करोड़ 39 लाख से भी ज्यादा केस लंबित हैं, जबकि यह वर्ष 1999 तक की रिपोर्ट है, इसमें कुछ 2000, 2001 की रिपोर्ट के अनुसार भी हैं यानि देश भर में इतने ज्यादा मुकदमें लंबित हैं, अभी ये आंकड़े पूरे नहीं हैं। सर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि आपके मंत्रालय में करोड़ों करोड़ जो पेंडिंग केस हैं उनका जल्दी से जल्दी निपटारा कराने के लिए आपके द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जो आपने यह जवाब दिया है, वह संतोषजनक नहीं है। क्या आप माननीय सदन को बता सकते हैं, आपका कम से कम एक साल से ज्यादा मंत्रिमंडल रहने वाला है, तो इस पीरिएड में आप इसमें क्या करने वाले हैं क्योंकि इन प्रकरणों में रैप से लेकर, मर्डर से लेकर बटाईदारों के बीस-बीस साल से मुकदमें पेंडिंग पड़े हैं, आप बताइए इनके लिए आप क्या करने जा रहे हैं?

श्री अरुण जेटली: सभापति जी, जो आंकड़े सदन के सामने रखे हैं, उसमें सबसे ज्यादा आंकड़े हैं, जो देश की सिविल अदालतों में हैं वह लगभग 68 लाख मुकदमें पेंडिंग हैं और क्रिमिनल अदालतों में लगभग 1 करोड़ 40 लाख से थोड़े से कम मुकदमें पेंडिंग हैं, यह संख्या पहले कुछ बढ़ी थी, लेकिन पिछले तीन-चार साल में इस प्रकार की संख्या लगभग 2 करोड़ से अधिक के आंकड़े पर आकर अब स्थाई हुई है। इस दिशा में सरकार ने कई कदम उठाए हैं। पहला कदम सरकार ने यह उठाया था, संसद ने भी उसकी स्वीकृति दी थी, कि जो कानूनी मुकदमें तय करने की प्रक्रिया है सिविल प्रोसीजर कोड, उसको छोटा करने का प्रोसेस हम लोगों ने किया है। उसका इंपलीमेंटेशन चालू हो चुका है। उसी प्रकार जहां तक क्रिमिनल ला का है, क्रिमिनल ला का प्रशासन न्यायपालिका देखती है, हालांकि जस्टिस विभाग में न आकर गृह मंत्रालय में आता है। गृह मंत्रालय ने उस दृष्टि से उसकी प्रक्रिया कैसे बहुत जल्दी पूरी की जा सके उसके लिए एक समिति का गठन किया था। इस वर्ष अपेक्षा है कि उस समिति की रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद जो भी संशोधन कानून में करने के लिए होंगे, उसको सदन के सामने हम लाएंगे। इसके अतिरिक्त लोक अदालतों का जो एक कानून हमने अभी बनाया था और आज से 13-14 साल पहले, जब भारद्वाज जी मंत्री थे, हमने एक

व्यवस्था आरम्भ की थी, वह प्रयोग सफल रहा है और लगभग 1.40 करोड़ मुकदमों का लोक अदालतों के माध्यम से निबटारा हुआ है और अब संसद ने कानून बनाकर यह तय किया है कि जितनी भी जन सुविधाओं की संस्थाएं हैं, पब्लिक युटिलिटीज़ हैं, वहां पर इस प्रकार की लोक अदालतें अनिवार्य हैं ताकि लोग वहीं अपना न्याय प्राप्त करने के लिए चले जाएं।

जहां तक आपने मर्डर, डकैती आदि इस प्रकार के मुकदमों के बारे में कहा, जो पुराने चले आ रहे हैं, तो देश में तीन साल से पुराने इस प्रकार के मुकदमे, जो सैशन अदालतों में चलते थे, वे 1.80 लाख के करीब थे। इसी के लिए दो वर्ष पूर्व हमने एक इनिश्येटिव लेकर 11वें फाइनेंस आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट्स को ग्रांट दी थी और हर प्रान्त से आग्रह किया था कि वे ऐसे केसिस का जल्दी निबटारा करने के लिए फास्ट ट्रेक अदालतों को बनाए। 1.80 लाख हाई क्राइम के पुराने मुकदमें उनके सामने रखे थे, अंतिम फिगर्स इस बारे में जो हमारे पास आए हैं उनके अनुसार उनमें से 77,000 के करीब केसिस डिस्पोज़ हो चुके हैं और उससे कन्विक्शन रेट में भी सुधार आया है।

श्री गया सिंह: सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि देश में टोटल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से नीचे के कितने जजों के पद खाली हैं और उनको भरने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं, इसके लिए आप क्या कोई टाइम बाउंड प्रोग्राम बता सकते हैं? इसी के साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि देश में जो श्रम न्यायालय हैं उनमें कितने ही जज हैं जो एक-एक साल या दो-दो साल से गए ही नहीं हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि उनके मुकदमे कौन देखेगा?

श्री अरुण जेटली: सभापति जी, जहां तक न्यायालयों की व्यवस्था है, इस बारे मैं मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में केवल एक स्थान रिक्त है और जब कभी वह स्थान भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश आएगी, उसको भर दिया जाएगा। हाई कोर्ट्स में लगभग 647 स्थान हैं, जिनमें से 512 पर इस वक्त लोग काम कर रहे हैं, 135 रिक्त हैं। उनको भरने के लिए सरकार के पास 65 सुझाव आए हैं, जिनके लिए कंसलटेशन की प्रक्रिया चल रही है और उनको भरने का प्रोसैस हम पूरा कर रहे हैं।

जहां तक देश भर की सबोर्डिनेट कोर्ट्स का सवाल है, वहां 2041 स्थान रिक्त हैं और उनको भरने की प्रक्रिया हर हाई कोर्ट को करनी पड़ती है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसलटेशन करके। उसकी नियुक्ति नोटिफाई स्टेट गवर्नमेंट करती है, लेकिन हाई कोर्ट के सुझाव पर करती है। इन रिक्त स्थानों को लेकर हर हाई कोर्ट को भी और स्टेट के चीफ मिनिस्टर को भी हम लिख रहे हैं। इस बारे में अधिकतर सक्रियता वहां के हाई कोर्ट को लेनी पड़ेगी ताकि इन स्थानों को जल्दी भरा जा सके।

SHRI HANSRAJ BHARDWAJ: Sir, I have carefully read the detailed reply which the hon. Minister has given. Some of the steps that have

been taken, like the Fast Track Courts, Lok Adalats, trimming of procedures etc., are very important, and we are happy about them. But the crux of the matter, according to my experience, is the pendency in district courts; a majority of these are criminal matters. About criminal matters, the tragedy is that our jails are overcrowded, and they are also unhygienic. This is a serious problem. Therefore, I suggest that you should discuss this matter with the States becuase all these courts are under the High Courts of various States, and you cannot directly deal with the judiciary at the lower level like you can do in Delhi High Court and the Supreme Court. It would be wiser for the Central Government to call the State Ministers and discuss with them how more judicial manpower and infrastructure could be given to the States. I think this matter is under the consideration of the Government and, if this can be expedited and the States can be given extra grants for having more judicial infrastructure and more manpower, you will be able to deal with this problem of pendency in the district courts also. The sooner it is done, the better. This is my suggestion.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, I am grateful to the hon. Member for his suggestion. But let me just clarify one fact. Even though the volumes are the largest as far as the subordinate courts are concerned, the disposal is also the larget as far as the subordinate courts are concerned. You have cases, not in lakhs, but almost in crores—1.3 to 1.4 crores—which are filed every year and the disposal rate of the subordinae courts is also virtually the same. Therefore, they are disposing of equal to the filling. The problem really is, you had 2.18 crores pending there; which has now come down to 2.07 crores. The real problem in the subordinate courts is, one is with regard to procedure and the other is with regard to more judges. The Supreme Court has also given a direction; the matter is under consideration of various State Governments, subject to the revenue constraints that they have. But the more serious problem of disposal is in High Courts, which has become the slowest layer of judicial functioning. In 1993, you had 19 lakh cases; today you have 35 lakh cases. High Courts are the only layer where the number of cases is gradually increasing and not coming down.

SHRI FALI S. NARIMAN: Sir, I congratulate the hon. Minister for giving such a detailed answer to the query. My query is limited to this. Today, the State, both the Centre and the States, is the biggest litigant,

in the High Courts, in the Supreme Court and in the District Courts. I would like to know first on the criminal side, is there any proposal with regard to plea-bargaining being introduced, as it has been introduced in many other countries, where an accused can plead guilty to a lesser charge and the other charge can be dropped? Now, that is the matter where you must authorise the counsel who appear for the State to necessarily enter into a plea-bargaining. On the civil side, Sir, I have noticed, it is my experience, that cases go on and on simply because Governments do not wish to seem to settle them. In our three-tier system, we have cases going on and individual litigants are put to a great harassment. Therefore, my question is, would you give authority to a set of responsible counsels who appear for the centre or for the States, in order that they may settle matters so that litigants get satisfaction at the earliet possible time?

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, the hon. Member, in the form of his question, has made two very important suggestions. With regard to plea-bargaining, this is the practice which is followed by several jurisprudences in the world. This question has been under serious consideration because the Home Ministry had appointed the Justice Malimath Committee to get into the reform of the entire criminal law procedure system. And this issue is under consideration of that Committee. They are going into it. In fact, I had interactions myself with that Committee, and this was one of the questions which I had raised with the Committee. They will, of course, have to balance it as to whether under the Indian set up, plea-bargaining itself may be a successful experiment or not, particularly when the conviction rate in high crime is so low, so the people involved in high crime may find it more profitable, or, better from their point of view to actually contest cases and get an acquittal rather than bargain a lesser punishment itself. This is the question where the Justice Malimath Commitee is consulting various experts, lawyers, police officers and others in the administration of law and order, and they would be making their recommendations.

With regard to Government's inability to settle cases, this is one of the reasons which prompted us to bring that law, before this hon. house, and this house has already passed that law, which is now being implemented, that at least, in the areas of all public utilities which are a major chunk of a State set-up, where people can actually go before the

Lok Adalats and, therefore, settle it, instead of going to court and filing cases. One of the weaknesses that we have noticed in the governmental machinery is, settling cases, particularly those which involves revenue consideration for the Government, there are a large number of civil servants and officers who are not prepared to take that responsibility on them due to future consequences. That is why this independent mechanism in utilities has been created. If this experiment succeeds, I am quite open to the suggestion of this being extended even to the Central and the State Governments.

DR. L.M. SINGHVI: Sir, we have great expectations from the hon. Minister. I hope, he has seen the Report submitted by the Standing Committee on this very issue, and many suggestions made therein. We would like a statement to be laid on the Table as to what is being done with regard to various suggestions made to the Government in that regard, especially, Sir, when the date of an office falling vacant is known well in advance, why is it that even as many as 135 or so vacancies are pending in High Courts? Secondly, what is being done to provide facilities for quick disposal so that courts can function effectively and expeditiously?

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, I would like to react to what the hon. Member, Dr. L.M. Singhvi, has said. Very valuable suggestions have been made by the Standing Commitee headed by Mr. Pranab Mukherjee with regard to the administration of justice. There are detailed guidelines in the memorandum, which require a recommendation for filling up of vacancies. The entire process has to start six months before a judicial officer or judge retires. But, I regret to say, this has never been done. Both the Chief Justice of India and the Law Minister have been repeatedly writing to the Chief Justices of the High Courts, requesting them for recommendation even after retirements. As I said, as against 135 vacancies today, we have only 65 recommendations under consideration. I would only react to Dr. Singhvi's statement instead of my making a suggestion. On an appropriate date, we are prepared to consult the leaders of various political parties on this issue. I have already started the process of informal consultation with some of them, so that the alternative system of appointment, as also the accountability in this matter, in terms of the National Judicial Commission, would be considered. In fact, it is one of the most valuable suggestions which the Standing Committee has made.

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Sir, instead of me, Mr. Thirunavukkarasu will put questions. He is a very senior lawyer and he is very eager to put questions. I seek your permission for that.

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU: Sir, we are told that several judges have been appointment to Lok Adalats and other courts in order to dispose of the cases quickly. I think, the number of judges alone is not sufficient. In a day, one judge disposes of a hundred cases and the other disposes of only two. What are the steps taken by this Government to improve the quality of judges?

SHRI ARUN JAITLEY: The hon. Member, besides his legislative experience, also has experience at the bar. He would know that India is a place where judges appoint judges and the Government doesn't appoint judges. Therefore, all steps, in this regard to ensure quality in matters of appointment, have really to be initiated by the judicial institution, as far as the present process of judicial appointments is concerned.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Sir, the reply given by the hon. Minister goes to show the fact that a large number of cases are pending. as far as the High Court of Kerala is concerned, it is the second in the country with 3,93,972 civil cases pending before it. There is a demend to set up a bench of the High Court at the State capital, Thiruvananthapuram. Even as per the recommendations of the Justice Jaswant Singh Commission, each State capital is entitled to have a High Court bench. In this context, I would like to know from the hon. Minister whether such a proposal is pending with you for setting up the High Court bench.

Also, with regard to reducing the volume of cases, another proposal has been made, as per the statement, for setting up of permanent Lok Adalats. Severe criticisms have been made from the Bar, Saying that it would confine itself to public utility services alone. I do agree, Sir. As far as the new era is concerned, the public utility service is being privatised. When it is privatised, I would like to know whether a private party would be compelled to accept the jurisdiction under the permanent Lok Adalat.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, as far as the proposal of benches of various High Courts is concerned, under our present law and the Constitutional provision as interpreted by the Supreme Court, the position is that it is only after the State Government and the High Court, both,

agree to make a recomendation with regard to creation of a bench of the High Court in the State itself, it is only then, that the proposal can be considered by the Central Government. As of today, as far as Tamil Nadu is concerned, there is a bench being constructed in Madurai; as far as West Bengal is concerned, there is a proposal, which has been accpeted, for creation of a bench in Jalpaiguri. Besides these two, no complete proposal for a bench in regard to any other High Court is pending.

With regard to the public utilities and Lok Adalats, Lok Adalats as a concept, as they have been existing, cover private institutions also. Lok Adalats, which were operating under the original regime, from 1988 onwards, have covered even private parties-matrimonial and other cases; they have been amicably resolved by the Lok Adalats. Therefore, in respect of any public utility, even if it goes into the hands of the private sector, as far as the present Act is concerned, it would have no implication, as far as the Lok Adalats are concerned.

दूरदर्शन की आय के लिए निर्धारित लक्ष्य

*87. **श्री राम जेठमलानी:**
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':†

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2003-2004 के दौरान दूरदर्शन की आय बढ़ाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस लक्ष्य की राशि क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए इस लक्ष्य की कोई राशि निर्धारित की थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वित्तीय वर्ष 2002-2003 के प्रथम नौ महीनों के दौरान दूरदर्शन की कुल आय कितनी थी?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

---

†सभा में यह प्रश्न श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' द्वारा पूछा गया।